पंजाब राज्य

बनाम

प्रेम सागर और अन्य।

(2008 की आपराधिक अपील संख्या 872)

13 मई, 2008

[एस. बी. सिन्हा और वी. एस. सिरपुरकर, जे. जे.]

आपराधिक कानूनः

सजा- निरधारण- सजा सुनाते समय अदालतों को उस पर लागू सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए-तत्काल मामले में, उच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों पर रोक नहीं लगाई कोई कानूनी सिद्धांत-अभियुक्तों को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ देते समय कोई पर्याप्त और ठोस कारण सामने नहीं आया-मुकदमे में विचारण न्यायालय द्वारा एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई पंजाब उत्पाद शुल्क की धारा 61(1) के तहत अपराध करने के लिए अदालत अधिनियम में संशोधन कर छह महीने की कैद और 100 रुपये का जुर्माना लगाया गया। 5000/- - पंजाब उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1914- धारा 61(1)- अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1958- दंड प्रक्रिया संहिता, 1973- एस.एस. 235, 248(2), 325, 360 और 361- भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 47 और 136.

उत्तरदाताओं को ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया था पंजाब उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1914 की धारा 61(1) के तहत अपराध करने के लिए, क्योंकि वे सामान 2000 लीटर रेक्टिफाईड स्पिरिट अवैध रूप से ले जाते हुए पकड़े गए थे। विचारण न्यायालय ने उन्हें एक साल की कैद की सजा सुनाई। उच्च न्यायालय विचार कर रहा है तथ्य यह है कि अपराध को 19 साल हो गए थे वापस, अभियुक्त को अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1958 का लाभ दिया। व्यथित होकर, राज्य ने तत्काल अपील दायर की।

अदालत ने अपील स्वीकार करते हुए मानाः

अभिनिर्धारित 1.1 सजा सुनाते समय अदालतों को अवश्य विचार करना चाहिए उस पर लागू सिद्धांतों पर विचार करें। यह दिमाग के प्रयोग की आवश्यकता है। सजा देने के उद्देश्य को भी ध्यान में रखना चाहिए। [पैरा 25] [589-एफ, जी]

1.2 क्या अदालत सज़ा सुनाते समय, निवारण या सुधार के सिद्धांत का सहारा लेगी या आनुपातिकता के सिद्धांत का आह्वान करेगी, यह निःसंदेह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। हालाँकि, ऐसा करते समय, अपराध की प्रकृति प्रतिबद्ध है। अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध की प्रकृति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सावर्जिनक स्वास्थ्य काे प्रभावित करने वाले अपराधों से सख्ति से निपटा जाए। उक्त

उद्येश्य के लिए कम्पनी को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 को लागू करने के उद्येश्य को ध्यान देना चाहिए। [पैरा 6-7] [578-सी,डी]

1.3 दंड प्रक्रिया संहिता में प्ली बार्गेनिंग के सिद्धांत को लागू करते समय भी कुछ प्रकार के अपराधों को इसके दायरे से बाहर रखा गया था। जबकि वाक्यों को लागू करते हुए, उक्त सिद्धांतों काे ध्यान में रखना चाहिए। [पैरा 7] [578-ई]

1.4 संसद, सजा पर सुनवाई का प्रावधान कर रही है, जैसा कि धारा 235, की उपधारा (2), धारा 248 की उपधारा (2), धारा 325 के साथ-साथ संहिता की धारा 360 एवं 361, 1973 ने कुछ सिद्धांत निर्धारित किये हैं। उक्त प्रावधान इस सिद्धांत को निर्धारित करते है कि अदालत को सज़ा सुनाते समय बड़ी संख्या में प्रासंगिक कारकों, आरोपी की समाज शास्त्रीय पृष्ठभूमि, उनमें से एक को ध्यान में रखना चाहिए। [पैरा 8] [578-एफएजीएएच]

1.5 यद्यपि अदालत को व्यापक विवेकाधिकार प्रदान किया गया है फिर भी इसका प्रयोग विवेकपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए। यह उन परिस्थितियों पर निर्भर करेगा जिनमें अपराध किया गया है और आरोपी की मानसिक स्थिति क्या है। आरोपी की उम्र भी प्रासंगिक है। [पैरा 8] [579-ए]

धनंजय चटर्जी उर्फ धन्ना बनाम स्टेट ऑफ प.बं. (1994) 2 एससीसी 220; जेंटेला विजयवर्धन राव और अन्य बनाम राज्य ए.पी. के [(1996) 6 एससीसी 241- शैलेश जसवंतभाई और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य (2006) 2 एससीसी 359; सेवक पेरुमल बनाम टीएन राज्य (1991) 3 एससीसी 471; मध्यप्रदेश राज्य बनाम बाला @ बलराम, (2005) 8 एससीसी1; मध्यप्रदेश राज्य बनाम गोविंद,(2005)8 एस.सी.सी. 12; कर्नाटक राज्य बनाम राजू 2007(11) स्केल 114; दलबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2000) 5 एससीसी 82; रतन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1979) 4 एस.सी.सी. 719-संदर्भित।

संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम बुकर 125 एस.सीटी. 757 पर; गैल बनाम संयुक्त राज्य 552 यू.एस. 2007-संदर्भित।

भारत सरकार के विधि मंत्रालय की रिपोर्ट, आपराधिक न्याय प्रणाली के सुधारों पर समिति, 2003; अपराध और न्याय का विश्वकोष, दूसरा संस्करण "केविन आर.रीट्ज़ द्वारा सजा के दिशानिर्देश" सजा और आपराधिक न्याय, 2005, एंड्रयू एशवर्थ द्वारा चौथा संस्करण; आपराधिक वाक्यः कानून के बिना आदेश (1973) माविरन फ्रेकल द्वारा "संघीय सजा दिशानिदर्शों की विफलताः एक रचनात्मक विश्लेषण' III 105 कॉलम.एल.रेव. 1315; "सजा आयोग के कार्य", "सजा आयोग आैर उसके दिशानिर्देश "(नॉर्थईस्टर्न यूनिवर्सिटी प्रेस, 1987), अध्याय 1. एंड्रयू वॉन हिर्श द्वारा;

"सजाः हाइमन ग्रॉस और एंड्रयू वॉन हिर्श, "डॉन एम. गॉटफ्रेडसन द्वारा "सजा दिशानिर्देश" पर निबंध-संदर्भित।

2. हालांकि सामान्य तौर पर यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए सजा की मात्रा में हस्तक्षेप नहीं करेगा] लेकिन इस प्रकृति के एक मामले में] उच्च न्यायालय ने एक गम्भीर त्रूटि की है] इसका हित यदि उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया जाता है और प्रतिवादी को छह महिने के अवधि के लिए साधारण कारावास और रूपये का जुर्माना लगाया जाता है तो न्याय की रक्षा की जाएगी। 5000/-प्रत्येक। [पैरा 26] [589-जी,519-ए]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील 2008 का नम्बर 872

चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के सीआरएल में दिनांक 7.7.20056 के अंतिम निर्णय और आदेश से। पुनरीक्षण क्रमांक 335/1992

कुलदीप सिंह, आर.के.पाण्डेय, मधूकर चौधरी आैर टी.पी.अपीलकर्ता की ओर से मिश्रा।

प्रतिवादियों की ओर से दिनेश वर्मा और डाॅ कैलाशचंद।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

एस.बी. सिन्हा, जेः 1. छुट्टी स्वीकृत।

2. हमारी न्याय व्यवस्था में हम विकास नहीं कर पाए हैं सजा के संबंध में कानूनी सिद्धांत।

श्रेष्ठ न्यायालय पुनः टिप्पणियाँ करने के अलावा उस अभिप्रायः और वस्तु पर ध्यान न दें जिसके लिए सज़ा दी गई है किसी अपराधी पर, कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किया था। अन्य विकसित देशों ने ऐसा किया है। कुछ तिमाहियों में, गंभीर निष्कर्ष। इस संबंध में चिंता व्यक्त की गई है। कुछ समितियाँ उदाहरण के लिएए माधव मेनन समिति और मलिमथ समिति ने सजा संबंधी दिशानिर्देश लागू करने की वकालत की है।

3. हालाँकि, इससे पहले, हम उक्त प्रश्न पर गहराई से विचार करते हैं मामले की सच्चाई पर गौर कर सकते हैं।

यहां उत्तरदाताओं को एक कमीशन के लिए दोषी ठहराया गया था 2000 लीटर रेक्टीफाइड स्प्रिट ले जाने पर पंजाब एक्साइज एक्ट की धारा 61(1) के तहत अपराध। उन्हें एक वर्ष की अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई गई।

4. हालाँकि, उच्च न्यायालय ने आक्षेप के कारण निर्णय को ध्यान में रखते हुए होने की उम्मीद है तथ्य यह है कि अपराध वर्ष 1987 में किया गया था और वर्ष 1992 में अपील खारिज कर दी गईए देना उचित समझा उत्तरदाताओं को स्वयं को सुधारने का अवसरए अवलोकन करते हुएः

''... आरोपियों को लंबे समय तक बहुत पीड़ा सहनी पड़ी है परीक्षण। मुख्य धारा में शामिल होने के बाद उनके पास होना ही चाहिए अपने द्वारा किये गये दुष्कर्म पर पश्चाताप व्यक्त किया करीब 19 साल पहले। उपरोक्त परिस्थितियों में और उनके किसी भी बुरे पूर्ववृत्त के अभाव में, ऐसा नहीं होगा उन्हें परिवीक्षा के लाभ से वंचित करना उचित होगा अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियमए 1958 के तहत और भेजने के लिए उन्हें इस स्तर पर जेल भेजा जाए।''

5. उक्त आधार पर, उत्तरदाताओं को रुपये के बांड को निष्पादित करने पर परिवीक्षा पर रिहा करने का निर्देश दिया गया था। ट्रायल जज की संतुष्टि के लिए समान राशि की एक-एक जमानत के साथ 20,000/- प्रोबेशन अधिकारी की कोई रिपोर्ट नहीं मांगी गई। प्रतिवादी की सामाजिक पृष्ठभूमि पर ध्यान नहीं दिया गया। उनका व्यवसाय क्या था इस पर ध्यान नहीं दिया गया।

6. क्या अदालत सजा सुनाते समय निवारण या सुधार के सिद्धांत का सहारा लेगी या आनुपातिकता के सिद्धांत का सहारा लेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

हालाँकि, ऐसा करते समय, आरोपी द्वारा किए गए कथित अपराध की प्रकृति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले अपराधों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। उक्त उद्देश्य के लिए, अदालतों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 को लागू करने के उद्देश्य पर ध्यान देना चाहिए।

7. कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो हमारे सामाजिक ताने-बाने को छूते हैं। हमें खुद को याद दिलाना चाहिए कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता में प्ली बार्गेनिंग के सिद्धांत को पेश करते समय भी, कुछ प्रकार के अपराधों को इसके दायरे से बाहर रखा गया था। वाक्य लगाते समय उक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए।

8. सज़ा किसी अपराध की दोषसिद्धि पर दिया गया निर्णय है। किसी व्यक्ति को अपराध का दोषी ठहराए जाने के बाद इसका सहारा लिया जाता है। यह किसी भी न्याय वितरण प्रणाली का अंतिम लक्ष्य है। हालाँकि, संसद सजा पर सुनवाई का प्रावधान कर रही है, जैसा कि धारा 235 की उप-धारा (2) ए धारा 248 की उप-धारा (2), धारा 325 के साथ-साथ आपराधिक संहिता की धारा 360 और 361 से प्रतीत होता है। प्रक्रिया ने कुछ सिद्धांत निर्धारित किये हैं। उक्त प्रावधान इस सिद्धांत को निर्धारित करते हैं कि अदालत को सजा सुनाते समय बड़ी संख्या में प्रासंगिक कारकों

को ध्यान में रखना चाहिए, अभियुक्तों में से एक होने की समाजशास्त्रीय पृष्ठभूमि।

हालाँकि न्यायालय को व्यापक विवेकाधिकार प्रदान किया गया है, लेकिन इसका प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। यह उन परिस्थितियों पर निर्भर करेगा जिनमें अपराध किया गया है और उसकी मानसिक स्थिति क्या है। आरोपी की उम्र भी प्रासंगिक है।

सजा का समाज पर क्या असर होगा यह एक सवाल है जिसे विधायिका ने अनुत्तरित छोड़ दिया है। उच्च न्यायालयों में बड़ी संख्या में ऐसे मामले सामने आए हैं जो सजा देने की नीति के संबंध में विसंगतियों को दर्शाते हैं। जबकि समान प्रकार के अपराध के लिए सजा की मात्रा न्यूनतम से अधिकतम तक भिन्न होती है, यहां तक जहां एक ही सजा दी जाती है, वहां लागू सिद्धांत अलग-अलग पाए जाते हैं। जुर्माना लगाने के संबंध में भी इसी तरह की विसंगतियां देखी गई हैं।

9. धनंजय चटर्जी उर्फ धन्ना बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में। [(1994) 2 एससीसी 220], इस न्यायालय ने कहाः

> ''15...उचित दंड देना वह तरीका है जिससे अदालतें अपराधियों के खिलाफ न्याय के लिए समाज की पुकार का जवाब देती हैं। न्याय की मांग है कि अदालतों को अपराध

के अनुरूप सजा देनी चाहिए ताकि अदालतें अपराध के प्रति सार्वजनिक घृणा दर्शा सकें...''

जेंटेला विजयवर्धन राव और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। [(1996) 6 एससीसी 24], धनंजय चटर्जी ;सुप्राद्ध का अनुसरण करते हुए, निवारण और प्रतिशोध के सिद्धांतों को बताता है लेकिन इसे सही या गलत के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। बहुत कुछ जजों के विश्वास पर निर्भर करता है।

10. शैलेश जसवन्तभाई और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य [(2006) 2 एससीसी 359, के हालिया फैसले में, इस न्यायालय ने कहाः

7. कानून सामाजिक हितों को नियंत्रित करता है, परस्पर विरोधी दावों और मांगों पर मध्यस्थता करता है। लोगों के व्यक्तियों और संपत्ति की सुरक्षा राज्य का एक आवश्यक कार्य है। इसे आपराधिक कानून के माध्यम से हासिल किया जा सकता है। निःसंदेह, एक अंतर-सांस्कृतिक संघर्ष है जहां जीवित कानून को नई चुनौतियों का उत्तर ढूंढना होगा और अदालतों को चुनौतियों का सामना करने के लिए सजा प्रणाली को ढालना होगा। अराजकता का संक्रमण सामाजिक व्यवस्था को कमजोर कर देगा और उसे खंडहर बना देगा। समाज की सुरक्षा और आपराधिक प्रवृत्ति पर रोक लगाना कानून का उद्देश्य होना चाहिए जिसे

उचित सजा देकर हासिल किया जाना चाहिए। इसलिए, कानून को ''व्यवस्था की इमारत की आधारशिला के रूप में समाज के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करना चाहिए। फ़्रीडमैन ने अपने लॉ इन चेंजिंग सोसाइटी में कहा है किः ''आपराधिक कानून की स्थिति जैसी होनी चाहिए- समाज की सामाजिक चेतना का एक निर्णायक प्रतिबिंब बनी हुई है।'' इसलिए, सजा प्रणाली के संचालन में, कानून को तथ्यात्मक मैट्रिक्स के आधार पर सुधारात्मक मशीनरी या निवारण को अपनाना चाहिए। चतुराई से मॉडुलन करके, सजा देने की प्रक्रिया जहां होनी चाहिए वहां कठोर होनी चाहिए, और जहां आवश्यक हो वहां दया से संयमित होना चाहिए। प्रत्येक मामले में तथ्य और परिस्थितियाँ, अपराध की प्रकृति, जिस तरह से इसकी योजना बनाई गई और प्रतिबद्ध किया गया, अपराध करने का मकसद, अभियुक्त का आचरण, इस्तेमाल किए गए हथियारों की प्रकृति और अन्य सभी परिस्थितियाँ शामिल हैं। प्रासंगिक तथ्य जो विचार के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे।

सेवक पेरुमल बनाम टीएन राज्य में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए। [(1991) 3 एससीसी 471], इस न्यायालय ने इसके अलावा माना कि अपराध की प्रकृति और जिस तरीके से इसे निष्पादित या

प्रतिबद्ध किया गया था आदि को ध्यान में रखते हुए उचित सजा देना हर अदालत का कर्तव्य है।

11. यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि इस न्यायालय ने कुछ मामलों में अभियुक्तों को सजा सुनाने के मामले में अपनाए गए पैटर्न की कड़ी आलोचना की। [मध्य प्रदेश राज्य बनाम बाला/बलराम,(2005) 8 एससीसी 1 और मध्य प्रदेश राज्य बनाम गोविंद, (2005) 8 एससीसी 12] देखें।

12. हाल ही में, कर्नाटक राज्य बनाम राजू [2007 (11) स्केल 114], जहां मामले के तथ्य यह थे कि ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी को धारा 376 के तहत नाबालिग के बलात्कार के लिए दोषी ठहराने के बाद सात साल की हिरासत की सजा दी थी। भारतीय दंड संहिताः अपील पर, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी की सजा को घटाकर साढ़े तीन साल कर दिया।

इस न्यायालय ने माना कि ऐसे मामले में जहां 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के साथ बलात्कार किया जाता है, सामान्य सजा 10 साल से कम कठोर कारावास नहीं है, हालांकि असाधारण मामलों में ''विशेष और पर्याप्त कारणों से' 10 साल से कम की सजा होती है। सश्रम कारावास की सजा भी दी जा सकती है। इस प्रकार, यह राय दी गई कि आरोपी या पीड़ित की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, धर्म, नस्ल, जाति या पंथ सजा नीति में अप्रासंगिक विचार हैं। क़ानून के तहत निर्धारित सज़ा को कम करने के

लिए न्यायाधीशों को किस हद तक विवेकाधिकार होना चाहिए, यह एक जटिल प्रश्न बना हुआ है।

हालाँकि, भारत में हमेशा यह विचार रहा है कि सज़ा अपराध के अनुपात में होनी चाहिए। हालाँकि, सभी स्थितियों में उक्त सिद्धांत की प्रयोज्यता पर सवाल उठ सकते हैं। प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायिक विवेक का प्रयोग निष्पक्षता से किया जाना चाहिए।

13. हम यह भी देख सकते हैं कि दलबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य [(2000) 5 एससीसी 82] में ए इस न्यायालय ने राय दी थीः

> ''13. भारत में सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती प्रवृत्ति और पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए विनाशकारी परिणामों को ध्यान में रखते हुए, आपराधिक अदालतें आईपीसी की धारा 304ए के तहत अपराध की प्रकृति को पीओ अधिनियम की धारा 4 के उदार प्रावधानों को आकर्षित करने वाला नहीं मान सकती हैं। ऑटोमोबाइल को तेजी से या लापरवाही से चलाने के कारण हुई मौत के अपराध के लिए दी जाने वाली सजा की मात्रा पर विचार करते समय, प्रमुख विचारों में से एक निवारण होना चाहिए। एक पेशेवर ड्राइवर लगभग पूरे कामकाजी घंटों के दौरान ऑटोमोबाइल

के एक्सीलेटर को पैडल चलाता है। उसे खुद को लगातार सूचित करना चाहिए कि जब उसका पैर गतिमान वाहन के पैडल पर हो तो वह एक पल की भी ढिलाई या असावधानी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह यह सोचकर जोखिम नहीं उठा सकता और न ही उसे ऐसा करना चाहिए कि जरूरी नहीं कि तेज गति से गाड़ी चलाने से कोई दुर्घटना होय या यदि कोई दुर्घटना घटित होती है तो आवश्यक नहीं है कि इसके परिणामस्वरूप किसी मनुष्य की मृत्यु होय या यदि ऐसी मृत्यु होती भी है तो उसे अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता हैः और अंत में यह कि अगर उसे दोषी भी ठहराया जाता है तो अदालत उसके साथ नरमी से पेश आएगी। उसे हमेशा अपने मन में यह डर रखना चाहिए कि यदि उसे लापरवाही से वाहन चलाने के कारण किसी इंसान की मौत का दोषी ठहराया जाता है तो वह जेल की सजा से बच नहीं पाएगा। ऑटोमोबाइल की लापरवाह ड्राइविंग के कारण मोटर दुर्घटनाओं की उच्च दर को कम करने के लिए, विशेष रूप से ट्रायल कोर्ट के स्तर पर, अदालतें यही भूमिका निभा सकती हैं।''

रतन सिंह बनाम पंजाब राज्य [(1979) 4 एससीसी 719] में, इस न्यायालय ने कहाः

''5. फिर भी, सजा में सुधार की नीति होनी चाहिए। इस ड्राइवर को, यदि उसे एक अच्छा ड्राइवर बनना है, तो मानव जीवन और अंग पर संभावित चोट के विशेष संदर्भ में, यातायात कानूनों और नैतिक जिम्मेदारी में बेहतर प्रशिक्षण होना चाहिए। इसलिए, इस क्षेत्र में सजा इन घटकों के साथ होनी चाहिए। हम आशा करते हैं कि राज्य, जब ड्राइविंग अपराधों के लिए सजा दी जाएगी, तो बेहतर ड्राइविंग के साथ-साथ जिम्मेदारी की एक जीवंत भावना भी जोड़ देगा। हो सकता है, राज्य इस पर विचार कर सकता है, गरीब परिवारों वाले पुरुषों के मामलों में, उचित आवेदन पर कभी-कभी पैरोल और सुधारात्मक पाठ्यक्रम, पुराने नियमों की कठोरता के बिनाए जो सरकारी विवेक के अधीन हैं।''

14. भारत सरकार के कानून मंत्रालय, आपराधिक न्याय प्रणाली के सुधार पर समिति, 2003 की स्थापना भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली में बदलाव की सिफारिश करने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई थी।

इसने देखा था कि न्यायाधीशों को वैधानिक सीमा के भीतर सजा देने में व्यापक विवेक दिया गया था। यह भी राय थी कि चूंकि तथ्यात्मक स्थिति में सबसे उपयुक्त सजा का चयन करने में कोई मार्गदर्शन नहीं था, सजा देने में कोई एकरूपता नहीं थी क्योंकि विवेक का प्रयोग प्रत्येक

न्यायाधीश के निर्णय के अनुसार किया जाता था। इस प्रकार, समिति ने सजा देने में अनिश्चितता को कम करने के लिए सजा दिशानिर्देश बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसने सजा संबंधी दिशानिर्देश तय करने के लिए एक वैधानिक समिति की नियुक्ति की सिफारिश की।

15. डॉन एमः गॉटफ्रेडसन ने ''सजारू हाइमन ग्रॉस और एंड्रयू वॉन हिर्श' में ''सजा दिशानिर्देश'' पर अपने निबंध में कहाः

> ''आपराधिक न्याय साहित्य में और वास्तव में लोकप्रिय प्रेस में यह एक आम दावा है कि सजा देने में काफी ''असमानता'' है... ''असमानता'' शब्द एक विशेषाधिकार बन गया है और'' ''
>
> है इसके साथ न्यायाधीशों की ओर से पक्षपातपूर्ण या कपटपूर्ण प्रथाओं का अर्थ है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अन्यथा वैध आलोचना असमानता के रूप में संदर्भित अनुचित भिन्नता से उचित भिन्नता को अलग करने में विफल रही है। वाक्यांश ''अनुचित असमानता'' को प्राथमिकता दी जा सकती हैः सभी सजा भिन्नताओं को अनुचित या असमान नहीं माना जाना चाहिए। इसमें से अधिकांश अपराध औरध्या अपराधी की अलग-अलग विशेषताओं में गंभीरता की अलग-अलग डिग्री को उचित रूप से दर्शाता है।

स्वभावगत भिन्नता जो अपराधी की अनुमेय, तर्कसंगत रूप से प्रासंगिक और समझने योग्य विशिष्ट विशेषताओं पर आधारित है और अपराध पूरी तरह से उचित, लाभकारी और उचित हो सकता है, जब तक कि परिवर्तनशील गुणों की सावधानीपूर्वक निगरानी की जाती है या समय के साथ स्थिरता और वांछनीयता पर ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा, चूंकि कोई भी दो अपराध या अपराधी एक जैसे नहीं होते हैं, भिन्नता को असमानता के रूप में लेबल करने में आवश्यक रूप से एक मूल्य निर्णय शामिल होता है - अर्थात, एक व्यक्ति के लिए असमानता दूसरे व्यक्ति के लिए उचित भिन्नता हो सकती है। ऐसा तभी होता है जब इस तरह की भिन्नता समान अपराध करने वाले समान अपराधियों के लिए अलग-अलग वाक्यों का रूप ले लेती है, तभी इसे असमान माना जा सकता है''

[जोर दिया गया]

विद्वान लेखक आगे कहते हैंः

''कई न्यायालयों में, न्यायिक विवेक लगभग असीमित है कि किसी व्यक्ति को कैद किया जाए या नहींः और केवल

वैधानिक अधिकतम सीमा से बंधा हुआ है, सजा की लंबाई के संबंध में विवेक की एक विस्तृत श्रृंखला छोड़ दी गई है।''

16. केविन आर. रिट्ज इनसाइक्लोपीडिया ऑफ क्राइम एंड जस्टिस, दूसरे संस्करण ''सजा दिशानिर्देश'' में कहा गया हैः

''सभी दिशानिर्देश क्षेत्राधिकारों ने ऐसे नियम बनाने को आवश्यक पाया है जो सजा के समय तथ्यात्मक मुद्दों की पहचान करते हैं जिन्हें दिशानिर्देशों के तहत हल किया जाना चाहिए, जो संभावित रूप से सजा के फैसले के लिए प्रासंगिक हैं, और जिन्हें निषिद्ध विचारों के रूप में देखा जाता है जिन पर ध्यान नहीं दिया जा सकता है सजा सुनाने वाली अदालतें। एक गर्म विवाद, जिसे सभी न्यायक्षेत्रों में अलग-अलग तरीके से संबोधित किया जाता है, वह यह है कि क्या दिशानिर्देश की सजा विशेष रूप से उन अपराधों पर आधारित होनी चाहिए जिनके लिए अपराधियों को दोषी ठहराया गया है (''दोषी अपराध'') या क्या एक दिशानिर्देश वाक्य में अतिरिक्त कथित आपराधिक आचरण को भी दर्शाया जाना चाहिए जिसके लिए औपचारिक दोषसिद्धि प्राप्त नहीं हुई है (''गैर-दोषी अपराध'')।

दिशानिर्देश डिजाइनरों के लिए सजा पर तथ्य-खोज का एक और कठिन मुद्दा यह है कि ट्रायल न्यायाधीशों को सजा देते समय अपराधियों की व्यक्तिगत विशेषताओं को कम करने वाले कारकों के रूप में विचार करने की अनुमति किस हद तक दी जानी चाहिए। उदाहरण के लिएः क्या प्रतिवादी एकल माता-पिता है और उसके घर में छोटे बच्चे हैं? क्या प्रतिवादी नशे का आदी है लेकिन नशीली दवाओं के इलाज के लिए अच्छा उम्मीदवार है? क्या प्रतिवादी ने अपराध से पहले आर्थिक, सामाजिक या शैक्षिक अभाव की स्थितियों पर काबू पाने के लिए संघर्ष किया है? क्या प्रतिवादी का आपराधिक व्यवहार कुछ हद तक उसकी युवावस्था, अनुभवहीनता या साथियों के दबाव का विरोध करने की उसकी विकृत क्षमता के कारण स्पष्ट हो सका? अधिकांश दिशानिर्देश बताते हैं, एक बार फिर स्वैच्छिक दिशानिर्देशों के साथ सभी न्यायक्षेत्रों को शामिल करते हुए, ट्रायल कोर्ट को ऐसे अपराधी विशेषताओं के न्यायाधीश के मूल्यांकन के आधार पर दिशानिर्देश सीमाओं के बाहर सजा देने की छूट देते हैं। कुछ राज्यों ने, इस डर से कि ऐसे कारकों पर अनियंत्रित विचार से नस्ल या वर्ग असमानताएं बढ़ सकती हैं, पात्र चिंताओं की सूची पर सीमाएं लगा दी हैं। (हालांकि,

ऐसे कारक अप्रत्यक्ष रूप से सजा को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि न्यायाधीशों को परिवीक्षा के लिए अपराधियों की विशेष ''अनुकूलता'' पर प्रस्थान का आधार बनाने की अनुमति है (फ़्रेज़, 1997).)''

17. एंड्रयू वॉन हिर्श और निल्स जेरेबॉर्ग ने वाक्य निर्धारण की प्रक्रिया को वाक्य निर्धारित करते समय आनुपातिकता निर्धारित करने के चरणों में विभाजित किया हैए अर्थात्ः

1. अपराध के मानक मामले से किन हितों का उल्लंघन या खतरा होता है- शारीरिक अखंडता, भौतिक समर्थन और सुविधा, अपमान से मुक्ति, गोपनीयता और स्वायत्तता।

2. एक विशिष्ट पीड़ित के जीवन स्तर पर उन हितों के उल्लंघन का प्रभाव- न्यूनतम कल्याण, पर्याप्त कल्याण, महत्वपूर्ण वृद्धि

3. अपराधी की दोषीता

4. एक उचित व्यक्ति द्वारा देखे गए वास्तविक नुकसान की दूरदर्शिता।

[एंड्रयू एशवर्थ, सजा और आपराधिक न्याय, 2005, चौथा संस्करण देखें]

18. यूनाइटेड किंगडम में दिशानिर्देश 1980 के दशक में दो अलग-अलग स्रोतों से उत्पन्न हुए। पहला मजिस्ट्रेट एसोसिएशन था, जिसने

निचली अदालतों के लिए सड़क यातायात अपराध दिशानिर्देश तैयार करने में पहला कदम उठाया। यह प्रक्रिया व्यापक और गहन हो गई है, जिससे कि 2004 से प्रभावी परिष्कृत दिशानिर्देशों का नवीनतम सेट उन सभी मुख्य अपराधों को कवर करता है, जिनका सामना उन अदालतों में होने की संभावना है। दिशा-निर्देशों का दूसरा स्रोत अपील न्यायालय था, जिसने अपनी पहल से, विशेष प्रकार के अपराधों, मुख्य रूप से अपराध के सबसे गंभीर रूप के निपटान में क्राउन कोर्ट के सजा सुनाने वालों को सहायता प्रदान करने के साधन के रूप में दिशानिर्देश निर्णय विकसित किए, जिसके लिए लंबी जेल की सजा का प्रावधान हैं। अपराध और विकार अधिनियम 1998 ने सजा दिशानिर्देशों की घोषणा में अपील की अदालत की सहायता और सलाह देने के लिए विविध सदस्यता वाली एक संस्थाए सजा सलाहकार पैनल (एसएपी) बनाई। पैनल और अपील अदालत ने 1999 से 2003 तक इस तरह प्रभावी ढंग से एक साथ काम किया, जिसके बाद सजा दिशानिर्देश परिषद (एसजीसी) की स्थापना की गई। आपराधिक न्याय अधिनियम 2003 द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण नवाचारों में से एक सजा दिशानिर्देश परिषद की स्थापना थी। परिषद, जो मुख्य रूप से लेकिन विशेष रूप से सजा देने वालों से नहीं बनी थी, ने सजा दिशानिर्देश जारी करने का काम संभाला, पैनल ने पहले की तरह ही कार्य किया, लेकिन अब अपील की अदालत के बजाय परिषद को सलाह दे रहा है। एसजीसी/एसएपी के सभी कर्मी अंशकालिक क्षमता में दिशानिर्देशों पर

काम करते हैंए लेकिन एक संयुक्त पूर्णकालिक सचिवालय द्वारा समर्थित होते हैं।

19. ''सजा पर आयोग'' का विचार 1970 के दशक की शुरुआत में मार्विन के फ्रेंकल के प्रभावशाली लेखन में खोजा जा सकता है, विशेष रूप से उनकी 1973 की पुस्तक क्रिमिनल सेंटेंसः लॉ विदाउट ऑर्डर में।

उन्होंने यह भी वकालत कीः

> ''समान स्थिति वाले अपराधियों पर लगाए गए दंडों में अधिक एकरूपता, सजा में नस्लीय असमानताओं और व्यक्तिगत न्यायाधीशों की प्राथमिकताओं के आधार पर व्यापक रूप से भिन्न वाक्यों सहित अस्पष्टीकृत असमानताओं में कमी के साथ''

[अपराध और न्याय का विश्वकोश, दूसरा संस्करण ''सजा संबंधी दिशानिर्देश'' केविन आर. रेइट्ज़ देखें]

20. 1984 के सजा सुधार अधिनियम ने सजा पर व्यापक न्यायिक विवेक और पैरोल की संभावना की विशेषता वाली अनिश्चित सजा की व्यवस्था के जवाब में बाध्यकारी सजा दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए अमेरिकी सजा आयोग का निर्माण किया। अधिनियम ने एक पारदर्शी, निश्चित और आनुपातिक सजा प्रणाली बनाने की मांग की, ज' ''अनुचित असमानता'' से मुक्त हो और सजा नीति और व्यक्तिगत सजा परिणामों पर

कांग्रेस के बीच शक्ति साझा करके ''निरोध, अक्षमता और अपराधियों के पुनर्वास के माध्यम से अपराध को नियंत्रित करने' में सक्षम हो। संघीय अदालतें, न्याय विभाग, और परिवीक्षा अधिकारी।

21. दिशानिर्देशों का हृदय एक पृष्ठ की तालिका हैः ऊर्ध्वाधर अक्ष अपराध के स्तर का तैंतालीस-बिंदु पैमाना है, क्षैतिज अक्ष आपराधिक इतिहास की छह श्रेणियों को सूचीबद्ध करता है, और निकाय कारावास के महीनों की सीमा प्रदान करता है अपराध और आपराधिक इतिहास का प्रत्येक संयोजन। एक सजा देने वाले न्यायाधीश को प्रासंगिक अपराध और इतिहास के स्तर की पहचान करने के लिए दिशानिर्देश मैनुअल में शामिल दिशानिर्देशों, नीति वक्तव्यों और टिप्पणियों का उपयोग करना होता है, और फिर उचित सजा सीमा की पहचान करने के लिए तालिका का संदर्भ लेना होता है। हालाँकि सभी मामलों में सजा अपराध के लिए क़ानून द्वारा अधिकृत अधिकतम सजा के बराबर या उससे कम होनी चाहिए, कुछ परिस्थितियों में दिशानिर्देश उस सजा से ऊपर और नीचे दोनों विचलन की अनुमति देते हैं जिसे अन्यथा अनुशंसित किया जाएगा।

22. 'संघीय सजा दिशानिर्देशों की विफलताः एक संरचनात्मक विश्लेषण' में [।।। 105 कॉलम.एल.रेव. 1315], फ्रैंक ओ. बोमन ने निम्नलिखित शब्दों में संघीय सजा दिशानिर्देशों की आलोचना कीः

''(1) दिशानिर्देश युग के दौरान संघीय आपराधिक प्रक्रिया द्वारा लगाए गए दंड की गंभीरता और आवृत्ति पहले की तुलना में काफी अधिक है।

(2) अधिकांश अपराधों के लिए संघीय अभियोजन और सजा नीतियों के प्रभाव को राज्य की नीतियों और प्रथाओं के प्रभाव से अलग करना मुश्किल और शायद असंभव है, अपराध दर को प्रभावित करने वाले व्यापक आर्थिक, जनसांख्यिकीय और सामाजिक रुझानों की तो बात ही छोड़ दें। (3) सजा नियम बनाने और व्यक्तिगत प्रतिवादियों को सजा देने की संघीय प्रक्रिया भटक गई है।''

23. संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम बुकर में [125 एस.सीटी. 757 पर] बुकर ने संघीय दिशानिर्देशों को पहले की तरह असंवैधानिक पाया, लेकिन उन्हें ''प्रभावी रूप से सलाहकार'' सजा नियमों की एक प्रणाली के रूप में बरकरार रखा।

24. हाल ही में गैल बनाम युनाइटेड स्टेट्स [552 यूएस 2007] के संयुक्त राज्य सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, अदालत को आठ सर्किट कोर्ट के फैसले की सत्यता का निर्धारण करना था जिसने गैल को 36 की सजा सुनाने के जिला अदालत के फैसले को पलट दिया था। महीनों की परिवीक्षा अवधि इस आधार पर कि संघीय सजा दिशानिर्देशों की सीमा के बाहर एक

सजा होनी चाहिए और इस मामले में असाधारण परिस्थितियों द्वारा समर्थित नहीं थी।

न्यायालय के फैसले को पलटते हुए यह राय दी गईः

"हालांकि किसी विशेष वाक्य और अनुशंसित दिशानिर्देश सीमा के बीच अंतर की सीमा प्रासंगिक है, अपील की अदालतों को विवेक के मानक दुरुपयोग के तहत सभी वाक्यों की समीक्षा करनी चाहिए - चाहे अंदर, बस बाहर, या दिशानिर्देश सीमा के बाहर।

(ए) क्योंकि दिशानिर्देश अब सलाहकार हैं, सजा के फैसलों की अपीलीय समीक्षा यह निर्धारित करने तक सीमित है कि क्या वे "उचित" हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम बुकर, 543 यू.एस. 220, और विवेक का दुरुपयोग मानक अपीलीय पर लागू होता है सज़ा के निर्णयों की समीक्षा। एक जिला न्यायाधीश को दिशानिर्देशों से किसी भी विचलन की सीमा पर विचार करना चाहिए और पर्याप्त औचित्य के साथ असामान्य रूप से उदार या कठोर सजा की उपयुक्तता की व्याख्या करनी चाहिए। एक अपीलीय अदालत विचरण की डिग्री को ध्यान में रख सकती है और दिशानिर्देशों से विचलन की सीमा पर विचार कर सकती है, लेकिन उसे

''असाधारण'' परिस्थितियों की आवश्यकता नहीं हो सकती है या ताकत निर्धारित करने के लिए मानक के रूप में प्रस्थान के प्रतिशत का उपयोग करके एक कठोर गणितीय सूत्र का उपयोग नहीं किया जा सकता है। किसी विशिष्ट वाक्य के लिए आवश्यक औचित्य।

(बी) एक जिला अदालत को लागू दिशानिर्देश सीमा की सही गणना करके शुरुआत करनी चाहिए।

दिशानिर्देश शुरुआती बिंदु और प्रारंभिक बेंचमार्क हैं लेकिन एकमात्र विचार नहीं हैं। किसी विशेष वाक्य के लिए दोनों पक्षों को बहस करने की अनुमति देने के बाद, न्यायाधीश को यह निर्धारित करने के लिए 18 यूएससी §3353(ए) के सभी कारकों पर विचार करना चाहिए कि क्या वे किसी भी पक्ष के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। वह यह नहीं मान सकता कि दिशानिर्देश सीमा उचित है, लेकिन उसे प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर व्यक्तिगत मूल्यांकन करना होगा। यदि वह दिशानिर्देश से बाहर के वाक्य पर निर्णय लेता है, तो उसे विचलन की सीमा पर विचार करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भिन्नता की डिग्री का समर्थन करने के लिए औचित्य पर्याप्त रूप से बाध्यकारी है।''

25. एंड्रयू वॉन हिर्श ने ''द सेंटेंसिंग कमीशन के कार्य , द सेंटेंसिंग कमीशन एंड इट्स गाइडलाइन्स (नॉर्थईस्टर्न यूनिवर्सिटी प्रेस, 1987), अध्याय 1.] में बीस साल से भी पहले एक सजा आयोग के केंद्रीय कार्यों का सारांश दिया था, यह देखते हुए कि कार्य थाः

> ''(1) सजा नीति की भविष्य की दिशा तय करने के लिए, पिछले सजा अभ्यास के अध्ययन से सूचितः
>
> (2) न्यायिक विवेक को समाप्त करने के बजाय उसकी संरचना करना, न्यायाधीशों को दिशानिर्देशों की व्याख्या करने और लागू करने और विशेष परिस्थितियों में उनसे विचलित होने की अनुमति देना और
>
> (3) सजा देने के लिए एक प्रमुख तर्क का चयन करना और उस पर दिशानिर्देश बनाना, ताकि सजा में स्थिरता को बढ़ावा दिया जा सके और असमानता को कम किया जा सके।''

उच्च न्यायालय अपना निर्णय किसी कानूनी सिद्धांत पर नहीं रखता कोई पर्याप्त या ठोस कारण नहीं आया है।

हमने अन्य देशों में इस संबंध में कानून के विकास को केवल इस बात पर जोर देने के लिए देखा है कि सजा सुनाते समय अदालतों को उस

पर लागू सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है। सजा देने के उद्देश्य को भी ध्यान में रखना चाहिए।

26. हालांकि सामान्य तौर पर, हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए सजा की मात्रा में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन इस प्रकृति के मामले में हमारी राय है कि उच्च न्यायालय ने गंभीर त्रुटि की है, हित यदि उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया जाता है और प्रतिवादी को छह महीने की अवधि के लिए साधारण कारावास और रुपये का जुर्माना लगाया जाता है तो न्याय की रक्षा की जाएगी। 5,000/- का जुर्माना लगाया जाता है, अन्यथा एक महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए कारावास भुगतना होगा।

27. अपील यहां पहले उल्लिखित सीमा तक स्वीकार की जाती है।

अपील की अनुमति

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सुश्री ज्योति शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।